'जॉइंट ट्रेड यूनियन कौंसिल, फ़रीदाबाद' का शांति-सद्भावना मार्च

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

31 जुलाई को नूंह ज़िले के मेवातियों ने नफ़रत-उन्माद के तूफ़ान को रोककर इतिहास रच दिया है। यह तारीख़ देश की फ़ासीवाद विरोधी तहरीक में एक तारीख़ी दिन नमूद हो चुका है। 9 साल के मोदी-राज में भयानक शोषण, अभूतपूर्व मंहगाई, बेरोज़गारी, दमन झेल रहे लोगों को मज़हब के ख़ूनी खेल में बांटकर एक बार फिर सत्ता हांसिल करने और उसके बाद देश के बचे-खुचे संसाधन चुनिंदा कॉर्पोरेट को सौंप देने का भाजपा-संघ का दांव उल्टा पड़ गया है। उस दिन के बाद से ही, समाज का अमन चाहने वाला हर तबक़ा खुलकर कट्टर हिन्दुत्ववादी गुंडों-उन्मादियों के ख़िलाफ़ आता जा रहा है। शुरुआत 'संयुक्त किसान मोर्चे' ने की और उसके बाद समस्त दलित, जाट, गूजर, अहीर-यादव समाज और फिर पूरी की पूरी 36 बिरादरी ने विहिप और बजरंग दल के गुंडों के सामन डटकर खड़े होने का ऐलान किया। मज़दूर नगरी फ़रीदाबाद, फासीवाद-विरोधी तहरीक की उस सुगंध से महकने म पीछे कैसे रह सकती थी। 'जॉइंट ट्रेड यूनियन कौंसिल फ़रीदाबाद' के आह्वान पर, 27 अगस्त को शाम 5 बजे प्याली चौक पार्क में एक शानदार शांति एवं सद्भावना सभा हुई जिसमें जॉइंट ट्रेड यूनियन घटकों के अलावा कई मज़दूर संगठनों जैसे 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' और 'इंक़लाबी मज़दूर केंद्र' तथा कई सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था।

सभा को सम्बोधित करते कॉमरेड सत्यवीर सिंह

सभा के पश्चात, प्याली चौक से हार्डवेयर चौक तक एक शानदार मार्च निकाला गया।

फ़रीदाबाद के मेहनतकश अवाम को सत्तर के दशक के वे पुराने दिन याद हो आए जब झाड़सेंतली गांव से बदरपुर बॉर्डर तक लाल झंडों का सैलाब नज़र आता था। सभी मज़दूर और सामाजिक संगठनों को इस संयुक्त तहरीक का हिस्सा बनने का अवसर देने के जॉइंट ट्रेड यूनियन कौंसिल के फ़ैसले का सबने स्वागत किया। इस मामले मे एटक के वरिष्ठ साथी आर एन सिंह के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। कार्यक्रम की एकता तथा कार्यक्रम के अलावा सैद्धांतिक डिबेट चलाने की विश्व सर्वहारा के महान नेता लेनिन की सीख का सम्मान करते हुए फ़ासीवाद विरोधी क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो भी ज़िम्मेदारी इस सम्बन्ध में हमें दी जाएगी उसे पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे।

सभा के अध्यक्ष थे एटक के वरिष्ठ नेता कामरेड विशम्भर सिंह तथा संचालन कर रहे थे सीटू के फ़रीदाबाद जिला सचिव कामरेड वीरेंद्र डंगवाल। सभा को इन नेताओं ने संबोधित किया; एटक से कामरेड आर एन सिंह, इंटक के कामरेड हुकम चंद बेनीवाल, एचएमएस के कामरेड आर डी यादव, बैंक इंप्लाइज यूनियन के प्रधान कृपाराम शर्मा, आईसीटीयू के पूर्ण लाल और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान करतार सिंह जागलान, इंक़लाबी मज़दूर केंद्र से कॉमरेड संजय मौर्य, पिछड़ा समाज संघ से रामफल जांगड़ा, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा से कामरेड सत्यवीर सिंह। ट्रेड यूनियनों ने नूंह की हिंसा को सुनियोजित और राज्य द्वारा प्रायोजित बताया। सारे के सारे समाज को मिलकर इस फासिस्ट हमले का विरोध करने का आह्वान किया। फरीदाबाद पुलिस समय रहते असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करती तो यह घटना नहीं होती। जब फ़ासीवादी ताक़तों का अजेंडा उल्टा पड़ गया और सारे का सारा समाज बजरंगदल-विहिप-भाजपा-संघ के उन्मादियों-दंगाईयों के ख़िलाफ़ गोलबंद होने लगा तब पुलिस को बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करना पड़ा। जब वह अपने लाव-लश्कर के साथ ज़हरीले विडियो जारी कर आग भड़का रहा था तब पुलिस-प्रशासन मूक दर्शक बना रहा।

30 जून को जब वह अपने बजरंग दल के गुंडों के साथ मिलकर हथियार लहराते हुए खोरी जमालपुर के पशुपालक हाजी जमात अली की गायों, बकरियां और गधों को जबरन बाई खेड़ा के जंगल से खोलकर ले गया था पुलिस ने तब भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

फिर से अधूरी कलश यात्रा को 28 अगस्त को फिर से पूरा करने के लिए 13 अगस्त को हथीन के पौंडरी गांव में पंचायत हुई थी जिसमें वक्ताओं ने ख़ूब ज़हर उगला और हिन्दू युवाओं को हथियार उठा लेने के लिए उकसाया गया। उन ज़हरीले दंगाईयों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हत्या का आरोपी मोनू मानेसर आज भी आज़ाद घूम रहा है।

नूंह में 31 जुलाई के बाद जो बुलडोज़र आतंक चला जिसमें हजारों गरीब मेहनतकशों की रोज़ी-रोटी को तबाह कर दिया गया जिसे माननीय चंडीगढ़ उच्च नयायालय ने भी 'नस्ली सफाए' की कार्रवाई करार दिया है, उसके विरुद्ध भी मज़दूरों को संगठित प्रतिरोध आंदोलन चलाने और पीड़ितों को सरकार से उचित मुआवज़ा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया गया। समाज में आपसी भाईचारा अटूट फ़ौलादी बनाना और देशभर में संयुक्त फासीवाद-विरोधी क्रांतिकारी आन्दोलन चलाना ही एक मात्र रास्ता है ज़ोरदार नारों के बीच इसी अहद के साथ सभा संपन्न हुई।

सभा में कुल 207 लोगों ने भाग लिया जिनका संगठनवार ब्यौरा इस तरह है:सीटू 68, क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा 51, एटक 35, इंटक 11, इंक़लाबी मज़दूर केंद्र 6 तथा अन्य संगठनों से 36।

चुनावी मौसम में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जा बरसे भोपाल व कोटा में

भूपेन्द्र यादव, श्रम मंत्री

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

जनता को छलने एवं बहकाने में माहिर मोदी सरकार के आदेश पर आजकल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र सिहं यादव मध्य प्रदेश व राजस्थान में पूरे मेहरबान होकर बरस रहे हैं क्योंकि आगामी तीन चार महीने में वहां की जनता से वोट लेने हैं।

मध्य प्रदेश के भोपाल तथा राजस्थान के कोटा में ईएसआई कॉरपोरेशन के एक-एक अस्पताल हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने का अर्थ, सुधी पाठक समझ लें कि जैसे सेक्टर आठ का ईएसआई अस्पताल हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और एनएच तीन का अस्पताल कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जा रहा है। अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों की हालत इतनी विकृत हो चुकी है कि कोई मरीज वहां जाकर राजी नहीं है और एनएच तीन के अस्पताल में मरीज क्षमता से दोगुने भरे हुए हैं।

मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी राज्य सरकार भोपाल वाले ईएसआई अस्पताल को ढंग से नहीं चला पा रही थी, जाहिर है इससे होने वाली मरीजों की दुर्दशा का बढ़ना स्वाभाविक था। अब चुनाव से चंद माह पूर्व वहां के लोगों को खुश करने के लिए मोदी के आदेश पर भूपेंद्र सिंह ने भोपाल के अस्पताल को राज्य सरकार से छीन कर अपने अधिकार में ले लिया और वहां तुर्त-फुर्त यानी विद्युत की गति से आवश्यक एवं वांछित स्टाफ की नियुक्ति कर डाली। ऐसी ही स्थिति कोटा वाले अस्पताल की भी चल रही थी, उसे भी कॉरपोरेशन ने अपने अधिकार में लेकर उसी गति से स्टाफ की नियुक्ति कर डाली।

अब पूछे कोई इस श्रममंत्री महोदय से कि उनकी नाक के नीचे मौजूद फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज-अस्पताल से उन्हें कौन से कांटे चुभते हैं जो यहां पर्याप्त एवं वांछित स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही? यह हाल तो तब है जब वे खुद अपने इलाज के लिए यहां आ चुके हैं। इतना ही नहीं 'मन की बात' करने, योगा दिवस मनाने अथवा पिकनिक करने तो जब चाहें इस संस्थान में आ पहुंचते हैं लेकिन इस अस्पताल को दरपेश जगह व स्टाफ एवं की कमी उन्हें क्यों नज़र नहीं आती? मंत्री महोदय को यह नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव तो यहां भी होने ही हैं।

फरीदाबाद के इस संस्थान की समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, मानेसर गुड़गांवां, हरियाणा के अन्य क्षेत्रों के अलावा दिल्ली व नोएडा तक के मरीजों को इलाज के लिए यहां भेजने में मुख्यालय में बैठे किसी अधिकारी को शर्म नहीं आती और मत्री महोदय बैठे-बैठे टुकुर-टुकुर ताकते रहते हैं। वह ये जानने और सोचने का प्रयास कतई नहीं करते कि फरीदाबाद पर ये सब जुल्म क्यों हो रहा है। और तो और, मरीज़ों की बात तो छोड़िए गुड़गांवा व दिल्ली के अस्पतालों के कपड़े भी धुलाई के लिए गाड़ियों में भरकर फरीदाबाद भेज दिए जाते हैं मानो ये मेडिकल कॉलेज न होकर धोबी घाट हो गया हो, गजब की बेशर्मी है। कारण यह बताया जाता है कि उनकी लॉंड्री की मशीनें खराब हो गई हैं। मूर्खालय में बैठे उन मूर्खों से कोई ये पूछे कि जिस दिन फरीदाबाद की मशीन खराब हो गई तो वे धुलाई के लिए कहां भेजेंगे। वैसे पूछने का यह काम है तो मंत्री महोदय का, लेकिन न जाने क्यों वे अपने मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं, उन्हें किस बात का डर है वे क्यों नहीं इन मूर्खों के कान को मरोड़ी लगाते?

रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन इत्यादि के लिए, पांच वर्ष पहले बहुत रो पीटकर इनकी मशीनें लगाई गई थीं। और अब हालत यह है कि पूरे एनसीआर के एमआरआई सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि के मरीजों की यहां लंबी लाइन लगा दी गई है, कई मरीजों को तीन-तीन महीने की तारीख मिलती है। पिछले दिनों एक गंभीर मरीज को एमआरआई कराने के लिए मानेसर से फरीदाबाद भेजा गया था, जिसने यहां तक आने जाने के दो हजार रुपये खर्च किए। उसे एक महीने की तारीख मिल गई तो रो पीट एवं झक मार कर 800 रुपये में अपना प्राइवेट एमआरआई करा लिया। मरीज के साथ क्या बनी, उसके दिल पर क्या बीती इससे मूर्खालय में बैठे मज़दूरों के खून पर पलने वाले हरामखोर कमिश्नरों को क्या लेना देना, कोई मरता है तो मरे उनकी बला से, उनके वेतन-भत्तों और अय्याशियों में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

काम का जितना बोझ एमआरआई व सीटी स्कैन पर जितना पड़ रहा है उसके चलते यह मशीनें भी बहुत लंबी चलने वाली नहीं हैं। क्यों नहीं समय रहते दिल्ली व गुड़गांवां में भी ऐसी ही मशीनें लगाकर मरीजों को राहत दी जाती। यहां के डॉक्टरों का कहना है कि मशीनें बेशक दिल्ली में लगा दें हम यहीं बैठे-बैठे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस तो उस श्रममंत्री के लिए होता है जो जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मूर्ख एवं हरामखोर अफसरों के सिर पर बैठाया गया है और उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलो श्रम मंत्री महोदय बेशक गुड़गांवां के मूल निवासी हैं और राज्यसभा से आते हैं इसलिए शायद वे अपने आपको आम जनता का नुमाइंदा न मानते हों लेकिन फरीदाबाद में जनता के चुने हुए सांसद, विधायकों एवं मंत्रियों को क्या सांप सूघे बैठा है जो उनकी बोलती बंद हुई पड़ी है। आए दिन मेडिकल कॉलेज में अपने उल्टे सीधे निजी कामों के लिए भटकने वाले इन नेताओं को क्या इस अस्पताल में मरीजों की होती दुर्दशा नज़र नहीं आ रही? क्या जन प्रतिनिधि होने के नाते तथा डबल इंजन की सरकार चलाने का दावा करने वाले इन नेताओं का कोई दायित्व नहीं बनता कि वे स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले को उच्चतम स्तर तक उठा कर अपने क्षेत्र की जनता को राहत दिलाएं?

ईएसआई अस्पताल प्रबंधन बीते दो साल से पैट स्कैन के लिए भटक रहा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल प्रबंधन बीते करीब दो साल से (पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी) पैट स्कैन सुविधा शुरू करने के प्रयास कर रहा है लेकिन मुख्यालय में बैठे निकम्मे, भ्रष्ट, जनविरोधी और हरामखोर अफसर लारे लप्पे देकर टालते जा रहे हैं। इस बार भी नवंबर में पैट स्कैन मशीन दिलाने का लारा अधिकारियों ने दिया है उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तो ऑर्डर ही नहीं दिया गया है, ऑर्डर देने के बाद भी मशीन की डिलीवरी- इंस्टालेशन में कम से कम ढाई महीने लग जाते हैं। मशीन लगने से न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि दिल्ली-एनसीआर के हजारों कैंसर मरीजों को बहुत फायदा मिलेगा।

ईएसआई मेडिकल कॉलेज से प्रतिवर्ष लगभग बारह सौ मरीजों को पैट स्कैन कराने के लिए रेफर किया जाता है। दिल्ली, गुड़गांवां, नोएडा, हिसार आदि शहरों को जोड़ लिया जाए तो यह संख्या पांच हजार मरीज प्रतिवर्ष तक पहुंच जाती है। महज बारह करोड़ रुपये की इस मशीन के लिए ईएसआई मेडिकल कॉलेज-अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग बीते दो वर्ष से मुख्यालय को पत्र लिख रहा है। मुख्यालय मे बैठे लूट कमाई में माहिर अधिकारी हर बार कोई रोड़ा अटका कर मशीन की खरीद टालते रहे। दरअसल, एक मरीज के पैट स्कैन पर लगभग 22,000 रुपये शुल्क लगता है, ये अधिकारी चाहते हैं कि मरीज बाहर से जांच कराके बिल लगाए ताकि भुगतान में कमीशन की मलाई खा सकें।

करीब 12 करोड़ रुपये कीमत की यह मशीन यदि ईएसआई मेडिकल-कॉलेज अस्पताल में लग गई तो दिल्ली-एनसीआर के करीब पांच हजार मरीजों को यह सुविधा तो उपलब्ध होगी ही, मशीन की कीमत भी एक साल के भीतर ही पूरी हो जाएगी। लेकिन मजदूरों की कमाई पर ऐश करने वाले यह भ्रष्ट और हरामखोर अधिकारी मशीन लगने दें तब तो। अब नवंबर में मशीन मिलने की संभावना जताई जा रही है लेकिन जब मशीन लगेगी तब ही माना जाएगा, क्योंकि मुख्यालय में बैठे निकम्मे अधिकारी बीते दो साल से अटका-लटका ही तो रहे हैं।

निगम सचिव ने विज्ञापन हटवा कर....

पेज एक का शेष

अवैध विज्ञापनों से प्रतिवर्ष अधिकारियों की जेब में लगभग पांच करोड़ रुपया जाता है। यह रुपया विज्ञापन माफिया के जरिए पहुंचता है। विज्ञापन माफिया पूरे शहर में अवैध रूप से होर्डिंग, गैंट्री, पोल और एडवारटाइजिंग डिस्प्ले ट्रक, वैन आदि चलाते हैं। एक होर्डिंग का एक महीने का किराया उसकी लोकेशन के आधार पर पचास हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक होता है। इसी तरह गैंट्री, पोल से भी प्रति माह लाखों की आमदनी होती है। डिस्प्ले ट्रक, वैन आदि का किराया भी लाखों रुपयों में होता है। इन अवैध विज्ञापनों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा निगम अधिकारियों तक पहुंचता है।

विज्ञापन विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा 2017 में हुआ था। यहां तैनात राजेंद्र सिंह नाम के कर्मचारी ने बताया था कि तत्कालीन एसडीओ उसे सत्ता पक्ष के राजनेताओं की होर्डिंग छोड़ कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों की होर्डिंग पोस्टर हटाने का आदेश देता है।

यही नहीं कुछ अस्पतालों और स्कूलों की अवैध होर्डिंग नहीं हटाने दी जाती। उसने इस तरह की कुछ अवैध होर्डिंग हटाईं तो एसडीओ ने उसका कॅरियर खत्म करने की धमकी दी थी। उसने बताया था कि विज्ञापन से नगर निगम को महज 26 लाख रुपये मिलते हैं जबकि इससे कहीं ज्यादा रकम अवैध विज्ञापनों के जरिए अधिकारियों में बंदरबांट होती है। राजेंद्र ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक की थी। वर्तमान में विज्ञापन की अवैध कमाई का यह आंकड़ा करीब पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बताया जा रहा है।